आबिद हुसैन समिति का प्रतिवेदन

442. **श्री कैलाश नारायण सारंग :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आबिद हुसैन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो वह प्रतिवेदन सरकार को कब प्राप्त हुआ था ; और

(ख) सरकार ने प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट सितम्बर, 1990 में प्राप्त हुई थी।

(ख) रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं ।

हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर सूत की आपूर्ति

443. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हथकरघा उद्योग को रियायती दरों पर सूत उपलब्ध कराती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान वितरण व्यवस्था दोषपूर्ण होने के कारण रियायती दरों का यह सूत हथकरघा उद्योग के बजाय अन्य क्षेत्रों को चला जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने का निश्चय किया है जिससे कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सरकार सूत के मूल्यों/श्रेणी के संबंध में कोई विनियोजन नहीं करती हैंक्यों कि सूत की मांग और आपूर्ति बाजार पर निर्भर रहती है। तथापि एक वित्तीय उपाय के रूप में हैंक के रूप में पैक किया गया सूत उत्पाद शुल्क से मुक्त होता है और यह सूत अधिकतर हथकरघा क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है।

(ख) समय-समय पर यह शिकायत मिलती रही है कि क्रास रील्ड हैंकयार्न को पावरलूम द्वारा प्रयोग करने की संभावना होती है ।

(ग) क्रास रील्ड हैंक यार्न पर शुल्क में छूट केवल हथकरघा के विकास के लिए पंजीकृत हथकरघा सहकारी समिति अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित किसी संगठन द्वारा की गई खरीद पर ही दी जाती है और उसका भुगतान ऐसी सहकारी समिति अथवा संगठन द्वारा बैंक एकाउंट से चैक द्वारा करती है ।

हथकरघा उद्योग का आधुनिकीकरण

444. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अखिल भारतीय बुनकर संघ ने हथकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण तथा बुनकरों के पुनर्वास के लिए एक निधि स्थापित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को स्वीकार करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत सरकार को अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर संघ, मद्रास से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हथकरघा बुनकरों के पुनर्वास और करघों के आधुनिकीकरण के लिए एक निधि स्थापित करने का सुझाव दिया है।

(ख) भारत सरकार हथकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकता और इसके विकास के लिए उपाय करने की आवश्यकता पर सहमत हैं । हथकरघा बुनकरों के पुनर्वास के संबंध में भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र में और इसके बाहर अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए वचनबद्ध है ।